

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एस.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1054/2019

1. बाबू शेख पुत्र रोशन शेख।
2. नूर शेख पुत्र बाबू शेख,
3. करीम पुत्र बाबू शेख,
4. रहीम पुत्र बाबू शेख,
5. चांद पुत्र बाबू शेख, सभी निवासी नवा रॉड गैस एजेंसी के पास थाना सांभर झील जिला। जयपुर राज.
6. मोहम्मद शेख पुत्र रोशन शेख, निवासी सराय मोहल्ला छोटा बाजार सांभर झील जिला। जयपुर राज.
7. नोशाद पुत्र मोहम्मद शेख, निवासी आलमपुरा मोहल्ला छोटा बाजार सांभर झील जिला। जयपुर राज.
8. सिराज पुत्र बंडू, निवासी आलमपुरा मोहल्ला छोटा बाजार सांभर झील जिला। जयपुर राज.
9. पीरू शेख पुत्र अब्दुल करीम शेख, निवासी के पास कन्हैया लाल अखाड़े नहीं छोटा बाजार सांभर झील जिला। जयपुर राज.

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से
2. अब्दुल सलाम उर्फ कालू पुत्र गफूर, निवासी मोहल्ला खारदा सांभर झील जिला. जयपुर राज.

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री दिनेश पारीक
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री महेंद्र मीना , पीपी
सुश्री वैष्णवी श्री अश्विन गर्ग के
लिए

माननीय श्रीमान. जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

आरक्षित तिथि : 09/04/2024

उच्चारण तिथि : 18/04/2024

प्रकाशनीय

1. यह याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 1 सांभर लेक, जिला जयपुर द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 12/2013 में पारित दिनांक 30.08.2018 के आदेश को चुनौती देती है, जिसके द्वारा शिकायतकर्ता प्रतिवादी द्वारा धारा 193 सीआरपीसी के तहत आरोपी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए दायर आवेदन को अनुमति दी गई है और तदनुसार धारा 147, 148, 341, 323, 325, 308 और 149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उनके खिलाफ संज्ञान लिया गया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और जांच के बाद

केवल आरोपी गुलाब , गफूर , रमजान , शहजाद , गफार सईद के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक , जिला जयपुर द्वारा 25.02.2023 के आदेश के तहत उनके खिलाफ संज्ञान लिया गया। वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि अपराध सत्रों द्वारा विचारणीय थे, इसलिए मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सांभरलेक की अदालत को सौंप दिया गया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि मामले के सौंपने के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 13.03.2013 को उन्हीं अपराधों के लिए उन आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया और उसके बाद मामले को आरोप तय करने के लिए पोस्ट किया गया। वकील ने प्रस्तुत किया कि इस स्तर पर, शिकायतकर्ता प्रतिवादी ने धारा 193 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया । बाकी आरोपियों यानी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए 27.01.2014 को। वकील ने कहा कि कानून के स्थापित प्रस्ताव को नजरअंदाज करते हुए, ऊपर बताए गए अपराधों के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लिया गया है। वकील ने कहा कि यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि किसी अपराध का संज्ञान लिया जाता है न कि अपराधी का। वकील ने कहा कि इस मामले में तीन बार संज्ञान लिया गया है, एक बार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा और दो बार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा। वकील ने कहा कि जब मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत को सौंपा

गया था और बाकी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान लिया गया था, जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था , तो शिकायतकर्ता और राज्य के पास संज्ञान लेने के लिए उचित आवेदन करने का अवसर उपलब्ध था, लेकिन उस स्तर पर ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। वकील ने कहा कि आवेदन बाद के चरण में प्रस्तुत किया गया था जिसे विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यानी ट्रायल जज ने गलती से अनुमति दे दी है। वकील का कहना है कि इन परिस्थितियों में, विद्वान ट्रायल जज द्वारा पारित आक्षेपित आदेश कानून की नज़र में वैधानिक रूप से टिकने योग्य नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धर्म पाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य , **2014 (3) SCC 306** मामले में और इस न्यायालय द्वारा शोदान सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (एसबी आपराधिक विविध याचिका संख्या **2281/2016**) मामले में पारित निर्णय का हवाला दिया है । वकील का कहना है कि उपरोक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर, इस न्यायालय का हस्तक्षेप उचित है और 30.08.2018 का आक्षेपित आदेश रद्द और निरस्त किए जाने योग्य है।

3. इसके विपरीत, विद्वान सरकारी वकील और शिकायतकर्ता के वकील ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि धारा 193 सीआरपीसी के अनुसार , सत्र न्यायालय द्वारा

उन आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया जा सकता है, जिनके खिलाफ जांच एजेंसी ने आरोप पत्र दायर नहीं किया है। वकील ने कहा कि जब याचिकाकर्ताओं के खिलाफ स्पष्ट और विशिष्ट सबूत मौजूद थे, तब भी उन्हें पुलिस ने छोड़ दिया था, इसलिए इन परिस्थितियों में, शिकायतकर्ता के पास उनके खिलाफ संज्ञान लेने के लिए धारा 193 सीआरपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। वकील ने कहा कि धारा 193 सीआरपीसी विद्वान सत्र न्यायाधीश को उन आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेने का अधिकार देती है, जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा है:

1. धर्मपाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, **2014 (3) एससीसी 306** में रिपोर्ट किया गया।
2. बलवीर सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (आपराधिक अपील संख्या **263/2016**)।
3. हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, **2014 Cr.LR. (SC) 310** में रिपोर्ट किया गया।
4. सरिता कुमारी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एसबी आपराधिक पुनरीक्षण संख्या **309/2016**)।
4. संबंधित पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'एफआईआर') के अवलोकन से पता चलता है कि यह याचिकाकर्ताओं सहित 13 से अधिक नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। यह एफआईआर अब्दुल सलाम द्वारा दर्ज कराई गई थी, जो घायल गफूर अहमद का पुत्र है। घायल गफूर अहमद के बयानों के अनुसार , याचिकाकर्ताओं सहित लगभग 15 लोगों ने उस पर हमला किया और उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोटें पहुँचाईं। घायल और शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के बयानों में सभी याचिकाकर्ताओं के नाम दर्ज थे। लेकिन जांच के बाद केवल 6 व्यक्तियों, अर्थात् गुलाब , गफूर , गफ्फार , रमजान , शहजाद और सईद को दिनांक 21.02.2013 को आरोप पत्र के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभर लेक, जिला जयपुर की अदालत में सुनवाई के लिए भेजा गया, जिन्होंने दिनांक 25.02.2013 के आदेश के तहत धारा 147, 148, 149, 323, 325, 341 और 308 आईपीसी के तहत अपराध के लिए उनके खिलाफ संज्ञान लिया और मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सांभर लेक की अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया।

6. मामले की सुनवाई के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उन्हीं आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया, जिन पर पुलिस ने उन्हीं अपराधों के लिए दिनांक 13.03.2013 के आदेश के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था और मामले को आरोप तय करने के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन निर्धारित तिथियों पर आरोपों पर बहस नहीं सुनी गई

और पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किए गए आरोपियों के अनुरोध के अनुसार आरोपों पर बहस सुनने के लिए मामले को एक तिथि से दूसरी तिथि तक स्थगित कर दिया गया था।

7. इसके बाद, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2-अब्दुल सलाम द्वारा धारा 193 सीआरपीसी के तहत शेष आरोपी व्यक्तियों यानी याचिकाकर्ताओं, जिनके खिलाफ पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था, के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया।

8. दलीलें सुनने के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 30.08.2018 के निर्णय/आदेश के तहत आवेदन को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 147, 148, 341, 323, 325, 308 और 149 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए संज्ञान लिया और उन्हें तलब किया।

9. दिनांक 30.08.2018 के उपरोक्त आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए इस न्यायालय के समक्ष इसका विरोध किया है।

10. याचिकाकर्ताओं की दलीलों का मुख्य मुद्दा यह है कि जब मजिस्ट्रेट ने 25.02.2013 के आदेश के तहत अपराध का संज्ञान ले लिया है और मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया है, जहां 13.03.2013 को आरोप-

पत्र दाखिल करने वाले आरोपियों के खिलाफ फिर से संज्ञान लिया गया, तो सीआरपीसी की धारा 319 के चरण का इंतजार किए बिना वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं है। वकील का दूसरा तर्क यह है कि अपराध का संज्ञान अपराधियों का नहीं लिया जाता है और जब अपराध का संज्ञान पहले ही दो बार 25.02.2013 और 13.03.2013 को लिया जा चुका है, तो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लेने वाला 30.08.2018 का बाद का आदेश कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में सत्र न्यायालय द्वारा धारा 193 सीआरपीसी के तहत संज्ञान लेने के चरण और शक्ति के बारे में परस्पर विरोधी विचार थे, जिसमें रणजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1998) 7 एससीसी 149, मेसर्स स्विन लिमिटेड बनाम दिल्ली राज्य और अन्य (2001) 6 एससीसी 670, राजिंद्र प्रसाद बनाम बशीर और अन्य (2001) 8 एससीसी 522, किशुन सिंह बनाम बिहार राज्य (1993) 2 एससीसी 16 और किशोरी सिंह बनाम बिहार राज्य (2004) 13 एससीसी 11 में रिपोर्ट किए गए मामले शामिल हैं। परस्पर विरोधी विचार यह था कि क्या सत्र न्यायालय द्वारा धारा 193 सीआरपीसी के तहत छोड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लिया जा सकता है या न्यायालय को धारा 319 सीआरपीसी के चरण तक इंतजार करना चाहिए ताकि स्पष्टता प्राप्त हो सके। इस बिंदु पर, मामला धर्मपाल (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को भेजा गया, जहां निम्नलिखित छह प्रश्न विचार के लिए आए, जो इस प्रकार हैं:

“(i) क्या पुलिस रिपोर्ट से यह पता चलने पर कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने के बाद, कमिटिंग मजिस्ट्रेट की कोई अन्य भूमिका है?

ii) यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से असहमत है और उसे विश्वास है कि रिपोर्ट के कॉलम 2 में जिन व्यक्तियों को रखा गया है, उनके विरुद्ध भी मुकदमा चलाया जा सकता है, तो क्या उसके पास उनके विरुद्ध भी समन जारी करने का अधिकार है ताकि पुलिस रिपोर्ट में दर्ज मामले के संबंध में उनके नाम नफे सिंह के साथ शामिल किए जा सकें?

iii) क्या अपीलकर्ताओं के विरुद्ध सम्मन जारी करने का निर्णय लेने के बाद, मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक था कि वह शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन करे तथा उन्हें सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए भेजने से पहले साक्ष्य ले या क्या ऐसी प्रक्रिया का पालन किए बिना उनके विरुद्ध सम्मन जारी करना न्यायोचित था?

iv) क्या सत्र न्यायाधीश मूल अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के रूप में धारा 193 सीआरपीसी के तहत समन जारी कर सकता है?

(v) मामला सत्र न्यायालय को सौंपे जाने पर, क्या सत्र न्यायाधीश संहिता की धारा 193 के अंतर्गत अलग से समन

जारी कर सकता है या उसे संहिता की धारा 319 के अंतर्गत समन जारी करने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी?

vi) क्या रणजीत सिंह का मामला (सुप्रा), जिसने किशुन सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्णय को रद्द कर दिया , सही ढंग से तय किया गया था या नहीं?

12. प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 इस याचिका में शामिल विवाद को तय करने में प्रासंगिक हैं और इसका उत्तर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा धर्म पाल (सुप्रा) के मामले में पारित निर्णय के पैरा 37 से 42 में दिया गया था और इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

37. प्रश्न 4, 5 और 6 कमोबेश आपस में जुड़े हुए हैं। प्रश्न 4 का उत्तर हाँ में होना चाहिए, अर्थात्, सत्र न्यायाधीश, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सौंपे जाने पर, धारा 193 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समन जारी करने के हकदार थे।

38. संहिता की धारा 193 सत्र न्यायालय द्वारा अपराधों के संज्ञान की बात करती है और निम्नानुसार प्रावधान करती है:-

"193. सेशन न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान.-
इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, कोई भी सेशन न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में तब तक नहीं लेगा जब तक कि मामला इस संहिता के

अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सुपुर्द न कर दिया गया हो।”

इस धारा में मुख्य शब्द हैं कि “कोई भी सत्र न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि मामला इस संहिता के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सुपुर्द न कर दिया गया हो।” उपरोक्त प्रावधान में यह आवश्यक है कि सबसे पहले किसी मामले को मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जाना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि मामला उसे सुपुर्द किए जाने के बाद ही सत्र न्यायालय आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अपराध का संज्ञान ले सकता है। यद्यपि, श्री दवे द्वारा यह सुझाने का प्रयास किया गया है कि धारा 193 में दर्शाया गया संज्ञान किसी अपराध के संज्ञान से नहीं, बल्कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रतिबद्धता आदेश से संबंधित है, हम धारा 193 के स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार की दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि सत्र न्यायालय उक्त धारा के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान ले सकता है।

39. यह हमें अगले प्रश्न की ओर ले जाता है कि क्या धारा 209 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को मामला सत्र न्यायालय को सौंपने से पहले अपराध का संज्ञान लेना आवश्यक था। यह सर्वविदित है कि किसी अपराध का संज्ञान केवल एक बार ही लिया जा सकता है। यदि मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है और फिर मामला सत्र न्यायालय को सौंपता है, तो अपराध का पुनः संज्ञान लेने और उसके बाद समन जारी करने का

प्रश्न विधि के अनुरूप नहीं है। यदि अपराध का संज्ञान लिया जाना है, तो यह मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है। संहिता की धारा 193 की भाषा बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि एक बार मामला विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंप दिए जाने के बाद, सत्र न्यायालय आरंभिक क्षेत्राधिकार और ऐसे क्षेत्राधिकार की धारणा से जुड़ी सभी बातें ग्रहण कर लेता है। इसलिए, धारा 209 के प्रावधानों को इस प्रकार समझा जाना चाहिए कि पुलिस रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकलने पर कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने में निष्क्रिय भूमिका निभाई जाती है। न ही मजिस्ट्रेट द्वारा आंशिक संज्ञान और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा आंशिक संज्ञान लिए जाने का कोई प्रश्न ही उठता है।

40. किशुन सिंह मामले (उपर्युक्त) में व्यक्त विचारों से सहमत होने में कोई संकोच नहीं है कि सत्र न्यायालय को किसी मामले को अपने सुपुर्द करने पर, उन व्यक्तियों के अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार है जिनका नाम अपराधी के रूप में नहीं है, लेकिन जिनकी मामले में संलिप्तता अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट होती है। अतः, साक्ष्य दर्ज किए बिना भी, धारा 209 के तहत सुपुर्दगी पर, सत्र न्यायाधीश पुलिस रिपोर्ट के कॉलम 2 में दर्शाए गए व्यक्तियों को, उसमें पहले से नामित व्यक्तियों के साथ, मुकदमे में उपस्थित होने के लिए बुला सकते हैं।

41. हम श्री दवे के इस निवेदन को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि सत्र न्यायालय के पास धारा 319 दंड प्रक्रिया

संहिता के तहत चरण तक प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, इससे पहले कि वह उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करे जिनके खिलाफ सत्र न्यायालय को मामला सौंपते समय विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए केस पत्रों में निहित सामग्रियों से प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

42. इस आशय के संदर्भ कि क्या रणजीत सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्णय किशुन सिंह के मामले (सुप्रा) में सही था या नहीं, का उत्तर यह मानते हुए दिया गया है कि किशुन सिंह के मामले में निर्णय सही निर्णय था और विद्वान सत्र न्यायाधीश, प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कमिटल आदेश के परिणामस्वरूप उन्हें प्रेषित रिकॉर्ड के आधार पर धारा 193 के तहत समन जारी कर सकते थे।

13. संवैधानिक पीठ द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बलवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में (2016) 6 एससीसी 680 में दोहराया गया था और पैरा 24 और 25 तत्काल मामले के निर्णय के लिए काफी प्रासंगिक हैं:

"24. उपर्युक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अब हम उन परिस्थितियों पर चर्चा कर सकते हैं जिनके तहत सत्र न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लिया गया था। यहाँ एक ऐसा मामला है जहाँ मजिस्ट्रेट को सौंपी गई पुलिस रिपोर्ट में, जांच अधिकारी ने अपीलकर्ताओं को अभियुक्तों के रूप में शामिल नहीं किया था। शिकायतकर्ता ने विद्वान मजिस्ट्रेट के

समक्ष अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भी संज्ञान लेने की प्रार्थना के साथ आवेदन दायर किया था। इस आवेदन पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने विधिवत विचार किया और उसे अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार, इस मामले में स्थिति यह नहीं है कि संहिता की धारा 173(8) के तहत दायर जाँच रिपोर्ट/ आरोप पत्र में अपीलकर्ताओं को शामिल किया गया हो और अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया हो कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। इसके विपरीत, पुलिस ने स्वयं अपनी अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मामला नहीं बनता। इस पर शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताई थी, जो चाहता था कि मजिस्ट्रेट इन अपीलकर्ताओं को भी समन करे और इसी उद्देश्य से शिकायतकर्ता ने संहिता की धारा 190 के तहत आवेदन दायर किया था। अपीलकर्ताओं ने उक्त आवेदन का उत्तर दिया था और दलीलें सुनने के बाद, आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। मजिस्ट्रेट। इससे पता चलता है कि मजिस्ट्रेट का आदेश पूरी तरह से सोच-समझकर पारित किया गया था जिसके तहत उन्होंने अपीलकर्ताओं के खिलाफ कथित अपराध का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और इसे केवल अपीलकर्ताओं के बेटे तक ही सीमित रखा। इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई। आम तौर पर, ऐसे मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायालय में भेजते समय 'निष्क्रिय भूमिका' निभाई थी। इस प्रकार, उन्होंने पूरी तरह से सोच-समझकर और प्रक्रिया में "सक्रिय भूमिका" निभाने के बाद संज्ञान लिया था। स्थिति अलग होती अगर मजिस्ट्रेट ने मामला करते समय शिकायतकर्ता के आवेदन को सत्र

न्यायालय में भेज दिया होता। इस परिदृश्य में, हमारी राय है कि यह एक ऐसा मामला होगा जहां मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया था। इसके बावजूद, सत्र न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा उसके समक्ष किए गए समान आवेदन पर संज्ञान लिया। आम तौर पर, कार्रवाई का ऐसा तरीका स्वीकार्य नहीं होगा।

25. अगला प्रश्न यह है कि क्या यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ऐसे आदेश को बाधित कर सकता है। हम पाते हैं कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध संज्ञान लेने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट का आदेश पुनरीक्षणीय है। पुनरीक्षण की यह शक्ति उच्च न्यायालय द्वारा, जो इस मामले में स्वयं सत्र न्यायालय होगा, या तो पीड़ित पक्ष द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से भी प्रयोग की जा सकती है। इस प्रकार, सत्र न्यायालय अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में आदेश पारित करने के लिए शक्तिहीन नहीं था। यदि उसने अपीलकर्ताओं को कोई अवसर दिए बिना, उनके विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेते हुए, आक्षेपित आदेश पारित किया होता, तो स्थिति भिन्न होती, क्योंकि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से इन अपीलकर्ताओं के पक्ष में एक मूल्यवान अधिकार प्राप्त हो गया था। हालाँकि, वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि यहाँ अपीलकर्ताओं को, जिन्होंने शिकायतकर्ता के आवेदन का उत्तर दायर किया था, उचित अवसर दिया गया था और सत्र न्यायालय ने उनकी दलीलें

भी सुनी थीं। इस कारण से, हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने और इस अपील को खारिज करने के इच्छुक नहीं हैं।"

14. धर्मपाल (सुप्रा) और बलवीर सिंह (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दोनों निर्णयों का सार यह है कि मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को सौंपने के बाद, सत्र न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 193 के तहत मूल अधिकारिता प्रदान की जाती है और यह पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल न किए गए अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए सक्षम है।

15. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आपराधिक विविध आवेदन संख्या 38681/2019 में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया गया:

"वर्तमान मामले में चूंकि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है और आरोप-पत्र के साथ संलग्न पुलिस दस्तावेजों पर विचार करने के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप तय किए गए हैं और मुकदमा शुरू हो चुका है, इसलिए निचली अदालत के लिए मामले का आगे संज्ञान लेना और उक्त आदेश द्वारा तीनों अभियुक्तों को तलब करना उचित नहीं होगा। उक्त आदेश द्वारा तीनों अभियुक्तों को तलब करना कानून के कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। निचली अदालत द्वारा सीआरपीसी की धारा 193 के तहत दूसरी बार लिया गया संज्ञान पूरी तरह से वैध और कानून द्वारा अनुमेय नहीं है। उक्त आदेश कानूनी रूप से उचित नहीं है और उक्त

आदेश से यह पता चलता है कि निचली अदालत ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। उक्त आदेश रद्द किए जाने योग्य है।"

16. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले में, सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया था और छूटे हुए अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप निर्धारित किए गए थे तथा मुकदमा शुरू किया गया था। नए अभियुक्तों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष इस आदेश का विरोध किया और न्यायालय का दृढ़ मत था कि निचली अदालत के लिए आगे संज्ञान लेना और अभियुक्तों को समन करना उचित नहीं था। यह माना गया कि सत्र न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 193 के अंतर्गत दूसरी बार लिया गया संज्ञान वैध नहीं था और कानून द्वारा अनुमेय नहीं था, इसलिए आदेश को रद्द कर दिया गया और उसे रद्द कर दिया गया।

17. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण को रफीउशशान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में आपराधिक अपील संख्या **1347/2021** (एसएलपी (सीआरएल) संख्या **1752/2020** से उत्पन्न) दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ रद्द कर दिया था:

“मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सौंपे जाने पर सत्र न्यायाधीश को धारा 193 सीआरपीसी के तहत समन जारी करने का अधिकार है। धारा 193 सीआरपीसी सत्र न्यायालय द्वारा अपराधों के संज्ञान की बात करती है। इस धारा के मुख्य शब्द हैं कि “कोई भी सत्र न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान आरंभिक अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के रूप में तब तक नहीं लेगा जब तक कि मामला इस संहिता के तहत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सौंप न दिया गया हो।”

सीआरपीसी के प्रावधान के अनुसार, किसी मामले को सबसे पहले मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंपा जाना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि मामला सत्र न्यायालय को सौंपे जाने के बाद ही, सत्र न्यायालय अपने आरंभिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपराध का संज्ञान ले सकता है। यह दलील कि धारा 193 सीआरपीसी में निर्दिष्ट संज्ञान किसी अपराध के संज्ञान से नहीं, बल्कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रतिबद्धता आदेश से संबंधित है, धारा 193 सीआरपीसी के स्पष्ट शब्दों के मद्देनजर विशेष रूप से खारिज कर दी गई कि सत्र न्यायालय उक्त धारा के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान ले सकता है।

किसी अपराध का संज्ञान केवल एक बार ही लिया जा सकता है। यदि मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है और फिर मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देता है, तो अपराध का नए सिरे से संज्ञान लेने और उसके बाद समन जारी करने की कार्यवाही करने का प्रश्न विधि सम्मत नहीं है। यदि अपराध का संज्ञान लिया जाना है, तो वह मजिस्ट्रेट या सत्र

न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है। संहिता की धारा 193 की भाषा बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि एक बार जब मामला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंप दिया जाता है, तो सत्र न्यायालय आरंभिक क्षेत्राधिकार और ऐसे क्षेत्राधिकार की धारणा से जुड़ी सभी बातें ग्रहण कर लेता है। इसलिए, संहिता की धारा 209 के प्रावधानों को इस रूप में समझा जाना चाहिए कि पुलिस रिपोर्ट के इस निष्कर्ष पर कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मजिस्ट्रेट मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने में एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है। न ही मजिस्ट्रेट द्वारा आंशिक रूप से संज्ञान और सत्र न्यायाधीश द्वारा आंशिक रूप से संज्ञान लिए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्त निष्कर्षों पर पहुँचने की प्रक्रिया में, इस न्यायालय ने धर्मपाल बनाम हरियाणा राज्य (सुप्रा) मामले में किशुन सिंह बनाम बिहार राज्य, (1993) 2 एससीसी 16 (एससीसी पृष्ठ 320, पैरा 40) में व्यक्त दृष्टिकोण को स्वीकार किया कि सत्र न्यायालय को किसी मामले को अपने अधीन करने के लिए, उन व्यक्तियों के अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार है जिनका नाम अपराधी के रूप में नहीं है, लेकिन जिनकी मामले में संलिप्तता रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों से स्पष्ट होगी। इसने विशेष रूप से यह माना कि संहिता की धारा 209 के तहत मामले को सौंपे जाने पर, सत्र न्यायाधीश पुलिस रिपोर्ट के कॉलम 2 में दर्शाए गए व्यक्तियों को, उसमें पहले से नामित व्यक्तियों के साथ, मुकदमे में उपस्थित होने के लिए बुला सकते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि उसी समय, न्यायालय ने धर्मपाल बनाम हरियाणा राज्य (सुप्रा) के मामले में यह भी माना कि यह मानना सही नहीं होगा कि पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर और यह देखते हुए कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मजिस्ट्रेट के पास मामले को सत्र न्यायालय को विचारण के लिए सौंपने के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं है और सत्र न्यायाधीश को उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले संहिता की धारा 319 के तहत चरण तक इंतजार करना होगा, जिनके खिलाफ सत्र न्यायालय को मामला सौंपते समय मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए केस पत्रों में निहित सामग्री से प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

XXXX XXXX XXXX

धर्मपाल मामले में दिए गए निर्णय के पैराग्राफ 7.4 में उठाए गए प्रश्न के अंतर्गत पूरी तरह से समाहित है। जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है, एक बार मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिए जाने पर, सत्र न्यायालय प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र ग्रहण कर लेता है और संहिता की धारा 193 के अंतर्गत उचित निर्देश पारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में होगा। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं है। इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बहाल करते हैं।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पुनः यही मुद्दा आया कि क्या धारा 319 सीआरपीसी के चरण तक प्रतीक्षा किए बिना मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 190 सीआरपीसी के तहत और सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 193 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त के खिलाफ संज्ञान लिया जा सकता है। यदि न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि आरोप पत्र दायर न किए गए अभियुक्त की प्रथम दृष्टया संलिप्तता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ संज्ञान लिया जा सकता है। कोई भी प्राधिकारी संज्ञान लेने पर किसी अभियुक्त को बुलाने में मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय की शक्ति या अधिकार क्षेत्र को सीमित या प्रतिबंधित नहीं करता है, जिसका नाम एफआईआर या पुलिस रिपोर्ट में शामिल नहीं हो सकता है। नाहर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में । (आपराधिक अपील संख्या **443/2022**) **16.03.2022** को तय किया गया, इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 20 में निम्नानुसार माना है:

"20. रघुवंश दुबे (सुप्रा), एसडब्ल्यूआईएल लिमिटेड (सुप्रा) और धर्मपाल (सुप्रा) के मामलों में , पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लेने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट की शक्ति या अधिकार क्षेत्र, पुलिस रिपोर्ट में नामित न किए गए अभियुक्त को अपराध की प्रतिबद्धता से पहले समन करने की शक्ति का विश्लेषण किया गया है। इस बिंदु पर एकमत दृष्टिकोण, इस तथ्य के बावजूद कि क्या संहिता की धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया

जाता है या धारा 193 के तहत सत्र न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, यह है कि उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों को तब तक इंतजार नहीं करना होगा जब तक कि मामला उस चरण तक न पहुँच जाए जब संहिता की धारा 319 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में समन करने के लिए किया जा सके, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में उसका नाम इस रूप में नहीं है। हम पहले ही अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं कि समन जारी करने का ऐसा अधिकार क्षेत्र ऐसे व्यक्ति के संबंध में भी प्रयोग किया जा सकता है जिसका नाम पुलिस रिपोर्ट में, चाहे अभियुक्त के रूप में हो या उसके कॉलम (2) में, बिल्कुल भी न हो, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि रिकॉर्ड में ऐसी सामग्री मौजूद है जो प्रथम दृष्टया उसकी संलिप्तता को प्रकट करती है। अपराध। कोई भी प्राधिकारी संज्ञान लेने पर किसी अभियुक्त को समन भेजने में मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय की शक्ति या अधिकार क्षेत्र को सीमित या प्रतिबंधित नहीं करता है, जिसका नाम एफआईआर या पुलिस रिपोर्ट में शामिल नहीं हो सकता है।

19. अतः, धर्मपाल (सुप्रा), बलवीर सिंह (सुप्रा), रफीउशन (सुप्रा) और नाहर सिंह (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णयों से यह स्पष्ट है कि सत्र न्यायालय को धारा 193 सीआरपीसी के तहत उन अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान लेने का अधिकार है, जिन्हें पुलिस ने छोड़ दिया है और जिन्हें जांच एजेंसी ने आरोप-पत्र के साथ अभियुक्त के रूप में शामिल नहीं किया है।

20. अब यह न्यायालय अभियुक्तों द्वारा उठाए गए अगले मुद्दे पर निर्णय करने के लिए आगे बढ़ता है कि मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा मामले को सौंपे जाने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा दो बार संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। यह तथ्य विवाद में नहीं है कि पुलिस द्वारा 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था और याचिकाकर्ताओं को पुलिस ने छोड़ दिया था और विद्वान मजिस्ट्रेट ने 25.02.2013 के आदेश के तहत उन 6 आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया और मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में भेज दिया, जहां 13.03.2013 के आदेश के तहत उन्हीं अपराधों के लिए फिर से उन्हीं 6 आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया गया और मामले को आरोपों पर बहस की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया। इसलिए, शिकायतकर्ता द्वारा धारा 193 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन छोड़ दिए गए आरोपियों यानी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें आरोप पत्र के साथ आरोपी के रूप में नहीं रखा गया था

21. पुलिस द्वारा आरोपित अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान लेने के बाद विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को न्यायालय को सौंपे जाने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा पुनः संज्ञान लेने का कोई कारण या अवसर नहीं था। अपर सत्र न्यायाधीश का ऐसा कृत्य एक अनियमितता

है, लेकिन कोई अवैधता नहीं है जो याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 461 के तहत कार्यवाही को अमान्य कर दे । अतः, इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों में कोई दम नहीं है।

22. याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने, मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए, धारा 319 सीआरपीसी के तहत निर्धारित चरण की प्रतीक्षा किए बिना, धारा 193 सीआरपीसी के तहत निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध सही ढंग से संज्ञान लिया है ।

23. उपर्युक्त चर्चाओं के मद्देनजर, निचली अदालत ने विवादित आदेश पारित करने में कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं की है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लेने में कोई त्रुटि नहीं की है।

24. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका असफल हो जाती है क्योंकि इसमें कोई दम नहीं पाया गया है और इसे खारिज किया जाता है।

25. अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, निरस्त माना जाता है। स्थगन आवेदन और सभी आवेदन (यदि कोई लंबित हों) भी अस्वीकृत माने जाते हैं।

(अनूप कुमार ढांड),जे

कुडी /18

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी